VAJIRAO & REDDY INSTITUTE
India's Top Potential Training Institute for IAS
+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

TODAY'S ANALYSIS

(आज का विश्लेषण)

(15 February 2025)

Sources:

The Hindu, The Indian Express, The Economics Times & PIB

Important News:

- **भारत-अमेरिका के मध्य 'व्यापार समझौते' का क्या मतलब होने वाले है?**
- **भारत-अमेरिका के मध्य 'ट्रांसफॉर्मिंग रिलेशनशिप यूटिलाइजिंग स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी (TRUST)' पहल**
- **MCQ**

ADDRESS:
19/1A Shakti Nagar, Nagiya Park Near Delhi University, New Delhi - 110007 (India)

भारत-अमेरिका के मध्य 'व्यापार समझौते' का क्या मतलब होने वाले है?

चर्चा में क्यों है?

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 14 फरवरी को इस साल पारस्परिक रूप से लाभकारी, बहु-क्षेत्रीय द्विपक्षीय व्यापार समझौते (BTA) के पहले चरण पर बातचीत करने और दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को मौजूदा 200 अरब डॉलर के स्तर से 2030 तक दोगुना करके 500 अरब डॉलर करने के लिए 'मिशन 500" की घोषणा की है।
- भारत-अमेरिका संयुक्त बयान के अनुसार, हालांकि मुक्त व्यापार समझौते के विपरीत BTA का दायरा बहुत सीमित है और यह समग्र व्यापार उदारीकरण के बजाय विशिष्ट वस्तुओं पर केंद्रित है, लेकिन भारत और अमेरिका ने व्यापार वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए "वरिष्ठ प्रतिनिधियों" को नामित करने की प्रतिबद्धता जताई है।
- दोनों देश "बाजार पहुंच बढ़ाने", टैरिफ और गैर-टैरिफ बाधाओं को कम करने की दिशा में काम करेंगे।

भारत के लिए BTA का क्या मतलब हो सकता है?

- यह पहली बार नहीं है जब भारत और अमेरिका व्यापार समझौते की संभावना तलाशने के लिए सहमत हुए हैं। उल्लेखनीय है कि अमेरिका के नेतृत्व वाला 14 सदस्यीय इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी (IPEF), जिसका भारत भी हिस्सा है, 2022 में IPEF के "व्यापार स्तंभ" पर सहमत नहीं हो सका क्योंकि इसमें टैरिफ में कटौती या अमेरिकी बाजार में पहुंच बढ़ाने की पेशकश नहीं की गई थी।
- इसके अलावा, राष्ट्रपति ट्रम्प ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस (GSP) कार्यक्रम को रोक दिया था, जो अमेरिका में 5 अरब डॉलर से अधिक मूल्य के भारतीय सामानों को शुल्क मुक्त पहुंच प्रदान करता था।
- व्यापार विशेषज्ञों का सुझाव है कि BTA के लिए भारत को अमेरिकी वस्तुओं के अधिक प्रवेश की अनुमति देने के लिए टैरिफ कम करने की आवश्यकता होगी, बजाय इसके कि अमेरिका बदले में टैरिफ लगाए, क्योंकि अमेरिका में औसत टैरिफ पहले से ही दुनिया में सबसे कम हैं।
- थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इंस्टीट्यूट (GTRI) ने कहा कि अमेरिका के साथ व्यापार समझौते के लिए यह सबसे अच्छा समय नहीं है, क्योंकि मौजूदा शासन एफटीए का सम्मान ही नहीं करता है।

भारत के टैरिफ 'बड़ी समस्या':

- भारत के टैरिफ को "बड़ी समस्या" बताते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि कारों जैसे अमेरिकी सामानों पर 70 प्रतिशत या उससे अधिक टैरिफ भारतीय बाजार तक पहुंच को सीमित करते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत-अमेरिका ब्रीफिंग में कहा, "भारत के साथ अमेरिका का व्यापार घाटा लगभग 100 अरब डॉलर है, और प्रधानमंत्री मोदी और मैं इस बात पर सहमत हुए हैं कि हम लंबे समय से चली आ रही असमानताओं को दूर करने के लिए बातचीत करेंगे"। अकेले वस्तुओं में, भारत के पास 2023-24 में लगभग 35 अरब डॉलर का अधिशेष था, जबकि इस साल के दौरान द्विपक्षीय व्यापार 120 अरब डॉलर था।
- राष्ट्रपति ट्रंप ने आगे कहा कि "हम एक निश्चित स्तर का खेल मैदान चाहते हैं, जिसके बारे में हमें लगता है कि हम वास्तव में हकदार हैं, और वह भी निष्पक्षता से ऐसा चाहते हैं। इसलिए हम इस पर बहुत मेहनत करने जा रहे हैं, और हम घाटे के साथ, तेल और गैस, तरलीकृत प्राकृतिक गैस (LNG) की बिक्री से बहुत आसानी से अंतर को पूरा कर सकते हैं, जिसकी हमारे पास दुनिया में किसी से भी अधिक मात्रा है"।

व्यापार घाटे को कम करने का दबाव:

- हालांकि भारत ने केंद्रीय बजट में कई वस्तुओं पर अपने मूल सीमा शुल्क को कम कर दिया है, पारस्परिक शुल्कों पर व्हाइट हाउस के एक बयान में बताया गया है कि कृषि वस्तुओं और मोटरसाइकिलों पर भारतीय शुल्क अमेरिका द्वारा भारतीय उत्पादों पर लगाए गए शुल्कों से काफी अधिक हैं।
- उल्लेखनीय है कि कोविड-19 महामारी के बाद अमेरिका के साथ भारत का माल व्यापार अधिशेष बढ़ रहा है, जो 2019-20 में 17.3 अरब डॉलर से दोगुना होकर 2023-24 में 35.33 अरब डॉलर हो गया है, साथ ही निर्यात बास्केट में उल्लेखनीय बदलाव हुआ है। जबकि इलेक्ट्रॉनिक और इंजीनियरिंग वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि हुई है, रत्न और आभूषण और परिधान जैसे पारंपरिक निर्यात काफी हद तक अपरिवर्तित रहे।
- इस बीच, पिछले पांच वर्षों में अमेरिका से भारत का आयात उसके निर्यात की तुलना में धीमी गति से बढ़ा है। 2023-24 में भारत को अमेरिकी निर्यात 42.19 अरब डॉलर तक पहुँच गया, जो 2019-20 में 35.81 अरब डॉलर था, जिसमें से अधिकांश पांच श्रेणियों में केंद्रित है: खनिज ईंधन (सबसे बड़ा खंड), इसके बाद कीमती और अर्द्ध-कीमती पत्थर, परमाणु रिएक्टर, विद्युत मशीनरी और विमान और पुर्जे।

भारत-अमेरिका 'ट्रांसफॉर्मिंग रिलेशनशिप यूटिलाइजिंग स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी (TRUST)' पहल:

परिचय:

- भारत और अमेरिका ने भारत-अमेरिका 'ट्रस्ट (ट्रांसफॉर्मिंग रिलेशनशिप यूटिलाइजिंग स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी: TRUST)' पहल की शुरुआत की घोषणा की, जो रक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अर्धचालक, क्वांटम, जैव प्रौद्योगिकी, ऊर्जा और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों के अनुप्रयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकार-से-सरकार, शिक्षा और निजी क्षेत्र के सहयोग को उत्प्रेरित करेगी, साथ ही सत्यापित प्रौद्योगिकी विक्रेताओं के उपयोग को प्रोत्साहित करेगी और सुनिश्चित करेगी कि संवेदनशील प्रौद्योगिकियों की सुरक्षा की जाए।
- उल्लेखनीय है कि 'ट्रस्ट' पहल भारत और अमेरिका को मौजूदा प्रयासों में तेजी लाने और महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं में चीन के प्रभुत्व का मुकाबला करने की स्थिति में भी लाता है।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

भारत-अमेरिका 'TRUST' पहल क्या है?

- TRUST पहल रक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अर्धचालक, क्वांटम कंप्यूटिंग, जैव प्रौद्योगिकी, ऊर्जा और अंतरिक्ष में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सरकारों, शिक्षाविदों और निजी क्षेत्र के बीच सहयोग को उत्प्रेरित करेगी।
- "ट्रस्ट" पहल के केंद्रीय स्तंभ के रूप में, दोनों देशों ने वर्ष के अंत तक एआई अवसंरचना में तेजी लाने पर अमेरिका-भारत रोडमैप पेश करने के लिए अमेरिकी और भारतीय निजी उद्योग के साथ काम करने की प्रतिबद्धता जताई।
- दोनों देशों ने 'इंडस इनोवेशन' के शुभारंभ की घोषणा की, जो सफल इंडस-एक्स प्लेटफॉर्म के आधार पर तैयार किया गया एक नया नवाचार सेतु है, जो अमेरिका-भारत उद्योग और शैक्षणिक साझेदारी को आगे बढ़ाएगा और अंतरिक्ष, ऊर्जा और अन्य उभरती प्रौद्योगिकियों में निवेश को बढ़ावा देगा, ताकि नवाचार में अमेरिका और भारत का नेतृत्व बना रहे और 21वीं सदी की जरूरतों को पूरा किया जा सके।

विश्वसनीय और लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं का निर्माण करने पर बल:

- दोनों देशों ने ट्रस्ट पहल के हिस्से के रूप में, सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिजों, उन्नत सामग्रियों और फार्मास्यूटिकल्स सहित विश्वसनीय और लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं का निर्माण करने के लिए भी प्रतिबद्धता जताई।

- इस प्रयास के हिस्से के रूप में, महत्वपूर्ण दवाओं के लिए सक्रिय दवा सामग्री के लिए अमेरिका सहित भारतीय विनिर्माण क्षमता का विस्तार करने के लिए सार्वजनिक और निजी निवेश को प्रोत्साहित करने की योजना बनाई है। ये निवेश अच्छी नौकरियां पैदा करेंगे, महत्वपूर्ण आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाएंगे और संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत दोनों में जीवन रक्षक दवाओं की कमी के जोखिम को कम करेंगे।

महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास में सहयोग:

- उभरती प्रौद्योगिकियों और उन्नत विनिर्माण के लिए महत्वपूर्ण खनिजों के रणनीतिक महत्व को पहचानते हुए, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका अनुसंधान और विकास में सहयोग को गति देंगे साथ ही खनिज सुरक्षा साझेदारी के माध्यम से, जिसके संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत दोनों सदस्य हैं, संपूर्ण महत्वपूर्ण खनिज मूल्य श्रृंखला में निवेश को बढ़ावा देंगे।
- दोनों देशों ने महत्वपूर्ण खनिजों की खोज, उत्खनन और प्रसंस्करण के साथ-साथ पुनर्चक्रण प्रौद्योगिकियों में सहयोग को गहरा करने के प्रयासों को तेज करने के लिए प्रतिबद्धता जताई है।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

- इस उद्देश्य से, एल्युमिनियम, कोयला खनन और तेल और गैस जैसे भारी उद्योगों से महत्वपूर्ण खनिजों (लिथियम, कोबाल्ट और दुर्लभ पृथ्वी सहित) को पुनर्प्राप्त करने और संसाधित करने के लिए एक नया अमेरिका-भारत कार्यक्रम 'रणनीतिक खनिज पुनर्प्राप्ति पहल' शुरू करने की घोषणा की।

TRUST राष्ट्रीय कार्यक्रमों पर निर्भर होगा:

- महत्वपूर्ण खनिजों और उन्नत सामग्रियों में भारत-अमेरिका सहयोग पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों द्वारा इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए - अन्वेषण और पुनर्चक्रण से लेकर प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान और विकास (R&D) - प्रमुख राष्ट्रीय कार्यक्रमों की घोषणा के बाद आया है।
- 2020 में, यूएस एनर्जी एक्ट ने आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाने और विस्तार करने तथा एक चक्रीय अर्थव्यवस्था बनाने के लिए महत्वपूर्ण खनिजों और सामग्रियों कार्यक्रम के लिए $675 मिलियन को अधिकृत किया।
- और जनवरी में, भारत ने सात वर्षों में 16,300 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय के साथ राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन को मंजूरी दी, जिसमें से लगभग 7,000 करोड़ रुपये महत्वपूर्ण खनिजों की खोज के लिए आवंटित किए गए हैं। इस मिशन

में महत्वपूर्ण खनिजों के पुनर्चक्रण का समर्थन करने के लिए प्रोत्साहन योजना के लिए 1,500 करोड़ रुपये भी शामिल हैं।

रणनीतिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण खनिज क्यों महत्वपूर्ण हैं?

- महत्वपूर्ण खनिज और REE रणनीतिक उद्योगों के लिए आवश्यक हैं, जिनमें रक्षा, अर्धचालक, क्वांटम कंप्यूटिंग, ऊर्जा और अंतरिक्ष शामिल हैं।
- नियोडिमियम, प्रेजोडायमियम और समैरियम जैसे तत्व मिसाइलों, लड़ाकू विमानों और रडार में उपयोग किए जाने वाले उच्च-प्रदर्शन वाले चुम्बकों के लिए महत्वपूर्ण हैं।
- लिथियम, कोबाल्ट और निकल ऊर्जा का उपयोग ऊर्जा भंडारण और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए उन्नत बैटरियों में किया जाता है, जबकि गैलियम और इंडियम अर्धचालक और AI हार्डवेयर में महत्वपूर्ण हैं।
- क्वांटम कंप्यूटिंग अल्ट्रा-शुद्ध सिलिकॉन और सुपरकंडक्टिंग सामग्रियों पर निर्भर करती है, जबकि यूरोपियम और टेरबियम जैसे REE बायोटेक इमेजिंग और मेडिकल डायग्नोस्टिक को बढ़ाते हैं।
- ऊर्जा में, REE चुम्बक पवन टर्बाइनों के लिए महत्वपूर्ण हैं, और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी गर्मी प्रतिरोधी मिश्र धातुओं और स्कैंडियम जैसी हल्की सामग्री पर निर्भर करती है।

- उल्लेखनीय है कि चीन वैश्विक REE उत्पादन के लगभग 70% और प्रसंस्करण बुनियादी ढांचे के अधिकांश हिस्से को नियंत्रित करता है, इसलिए विविध आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करना तकनीकी संप्रभुता और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। कुछ भंडारों के बावजूद भारत आयात पर निर्भर है, विशेष रूप से भारी दुर्लभ मृदाओं के लिए।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

MCQs

1. भारत और अमेरिका के मध्य हालिया चर्चा में रहे 'व्यापार समझौते' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

   1. इसके तहत दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को मौजूदा 200 अरब डॉलर के स्तर से 2030 तक 500 अरब डॉलर करने की योजना की घोषणा की गयी है।
   2. इसके तहत दोनों देश "बाजार पहुंच बढ़ाने", टैरिफ और गैर-टैरिफ बाधाओं को कम करने की दिशा में काम करेंगे।

   उपर्युक्त दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

   (a) केवल 1

   (b) केवल 2

   (c) 1 और 2 दोनों

   (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

   Ans:(c)

2. हाल ही में चर्चा में रहे 'इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी (IPEF)' की स्थापना कब की गयी है?

   (a) अक्टूबर 2021 में

   (b) मई 2022 में

   (c) दिसंबर 2022 में

   (d) मार्च 2023 में

   Ans:(b)

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

3. चर्चा में रहे 'IPEF से संबंधित व्यापार स्तंभों' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. इसमें अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं को कवर करने वाले चार स्तंभ शामिल हैं।

2. इसमें सहयोगी देशों को सभी चारों स्तंभ में भाग लेने की आवश्यकता है।

उपर्युक्त दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं।

Ans:(a)

4. भारत और अमेरिका ने 2022 में, 'महत्वपूर्ण और उभरती हुई प्रौद्योगिकी (iCET)' पर पहल को निम्नलिखित किस/किन क्षेत्रों में सहयोग के लिए शुरू किया था?

(a) सेमीकंडक्टर

(b) कृत्रिम बुद्धिमत्ता

(c) क्वांटम कंप्यूटिंग

(d) उपर्युक्त सभी क्षेत्र

Ans:(d)

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

5. चर्चा में रहे 'ट्रांसफॉर्मिंग रिलेशनशिप यूटिलाइजिंग स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी (ट्रस्ट)' पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. इस पहल के तहत, दोनों देश स्ट्रेटेजिक प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण में बाधाओं को कम करेंगे और उच्च तकनीक वाले वाणिज्य को बढ़ाएंगे।
2. यह पहल भारत और अमेरिका के मौजूदा प्रयासों में तेजी लाने और महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं में चीन के प्रभुत्व का मुकाबला करने के लिए लाया गया है।

उपर्युक्त दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं।

Ans:(c)